Inflation
(मुद्रास्फीति)

जब सामान्य कीमत स्तर अर्थात् सभी वस्तुएँ एवं सेवाओं की कीमतें औसतन लगातार बढ़े एवं मुद्रा की क्रयशक्ति कम हो।

अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति के उत्पन्न होने का मुख्य कारण मुद्रा की आपूर्ति Money Supply का अधिक होना है।

अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति के नियंत्रित हेतु RBI मौद्रिक नीति के द्वारा एवं सरकार राजकोषीय नीति के द्वारा मुद्रा आपूर्ति को कम करके मुद्रास्फीति को नियंत्रण करते हैं एवं इसे विस्फीति कहते हैं।

Deflation (अवस्फीति) :- जब सामान्य कीमत स्तर लगातार कम हो एवं मुद्रा की क्रय शक्ति बढ़े। यह तब होता है जब अर्थव्यवस्था मे मुद्रा आपूर्ति कम हो।

RBI एवं सरकार अवस्फीति का नियंत्रण मुद्रा आपूर्ति को बढ़ा कर करते हैं एवं इसे प्रत्यवस्फीति (Reflation) कहते हैं।

Inflation J.M Keyens

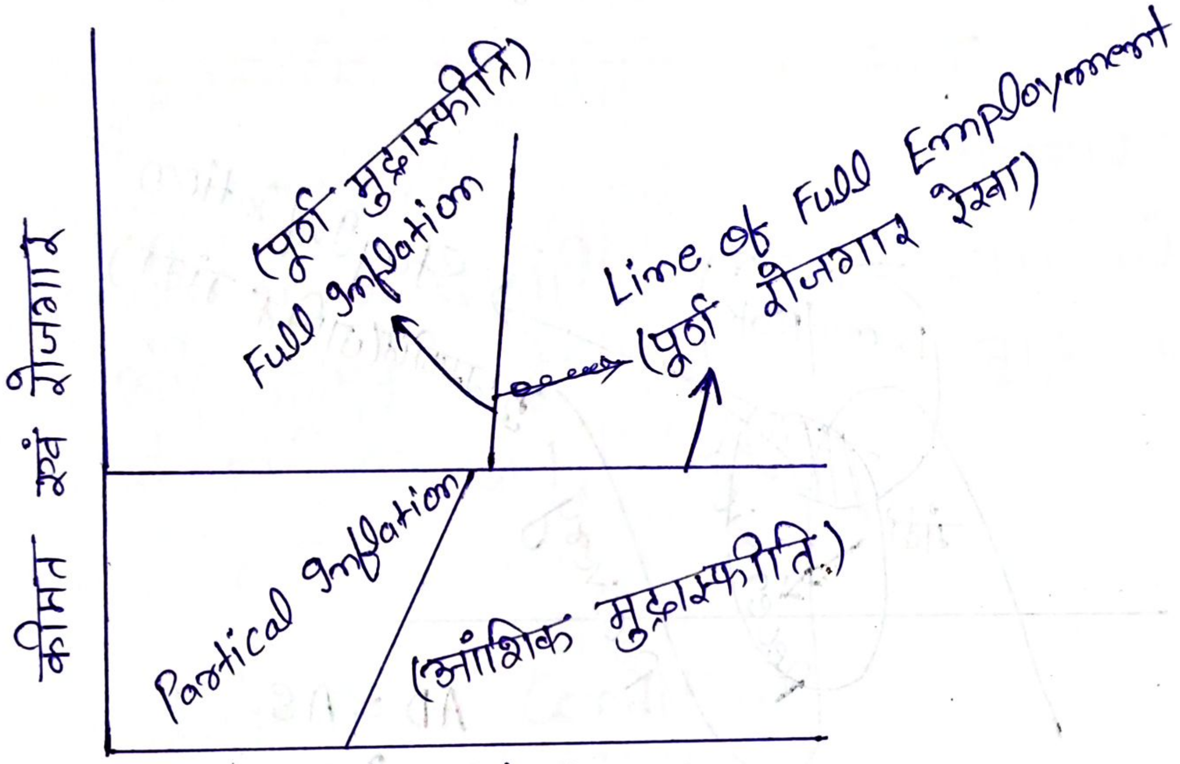

AD > AS

AD Aggregate Demand सम्पूर्ण मांग

AS Aggregate Supply सम्पूर्ण आपूर्ति

→ J.M Keyens ने कहा की पूर्ण मुद्रास्फीति पूर्ण रोजगार की रेखा के बाद उत्पन्न होती है।

मुद्रास्फीति के अर्थव्यवस्था पर प्रभाव

Business Cycle
व्यापार चक्र

AD > AS

MS ↑ AD > AS — Inflation

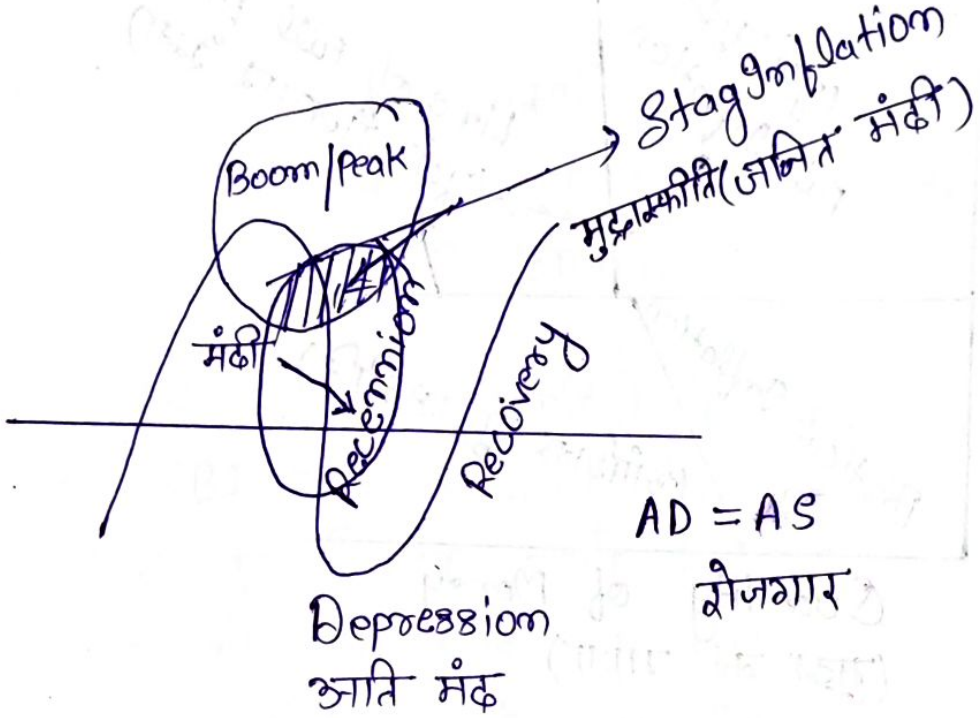

Boom / Peak → Money Supply ↑
AD > AS

MS↑ → AD > AS → Stock ↓

Depression MS↓ → AD > AS → अति मंदी

Stock ↑ → Product ↓ → रोजगार ↓ → आय ↓
(Jobless Growth)

⇒ **Stagflation (जनित मंदी) :–**

यह अर्थव्यवस्था वह अवस्था है जहाँ मुद्रास्फीति एवं मंदी एक साथ हो।
जब मुद्रास्फीति बढ़े लेकिन रोजगार कम हो या मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी बढ़े और कीमत वृद्धि दर आर्थिक वृद्धि दर से अधिक हो।

Economic Condition
आर्थिक स्थितियाँ

① Slow down

$Q_1 = 6\%$

$Q_2 = 5.5\%$

$Q_3 = 4\%$

$Q_4 = 3.5\%$

② Contraction

$Q_1 = 5\%$

$Q_2 = -2\%$ ⇒ जब एक वृत्तीय वर्ष में किसी एक Quter में आर्थिक समृद्धि दर (Negative) नकारात्मक होती है उसे Contraction कहते हैं।

$Q_3 = 4\%$

$Q_4 = 6\%$

③ Recession / Technical (मंदी)

$Q_1 = 5\%$
$Q_2 = -2\%$]
$Q_3 = -3\%$]
$Q_4 = 2\%$

जब एक वृतीय वर्ष में लगातार दो Qutar में आर्थिक समृद्धि दर नकरात्मक हो जाए Recession इसे तकनीकी मंदी भी कहते है।

④ Depression :- अति मंदी

जब मंदी अत्याधिक हो जाए और जब मंदी एव अवस्फीति एक साथ हो।

⑤ Melt down

Share Market अचानक गीर जाए।

मुद्रास्फीति के प्रकार :-

① सामान्य मुल स्तर में :- सामान्य कीमतों में परिवर्तन के आधार पर।

ⓐ रेंगती हुई मुद्रास्फीति

जब सामान्य कीमत स्तर 3% प्रतिवर्ष बढ़ती है।

ⓑ धीमी / मध्यम / चलती → 4 – 5%

ⓒ दौड़ती मुद्रास्फीति → 6 – 9%

⑤ Galloping Inflation द्रुत मुद्रास्फीति

दो या तीन अंकों में –

10%, 20%, 99% ....

⑥ Hyper Inflation (अति मुद्रास्फीति)

1000% से अधिक

जब सामान्य कीमत स्तर रातों-रात बढ़े

जब लोगों का देश की मुद्रा पर से विश्वास न हो सके।

जैसे – हंगरी – 1946

जिम्बाबे – 2004

वेनुजएला – 2018

Monetary Policy Frame Work Agreement

Inflation Targetting Fram Work

मुद्रास्फीति का लक्षित ढाँचा / मौद्रिक नीति रूपरेखा

⇓

मुद्रास्फीति के लक्ष्य को सरकार RBI से सलाह लेकर निर्धारित करती है।

यह पांच वर्षों के लिए होता है।

इसे 2016 से प्रारम्भ किया गया

2016 – 21
2021 – 26 | 4%, ±2%

वर्तमान मे भारत के GDP मे योगदान

$ 3.469 Trillian

GDP

- Primary Sector — 18.8%
- Secondary Sector — 28.2%
- Teritary Sector — 53%

भारत की GDP मे श्रमकों का योगदान :-

Primary Sector — 42.6%

Secondary Sector — 25.12%

Teritary Sector — 32.28%

On the Basis of Cause of Inflation
मुद्रास्फीति के कारणों के आधार पर

① **मांग जनित (Demand-Pull)**

जब अर्थव्यवस्था मे मांग बढने के कारण मुद्रास्फीति बढ़ती है।
इसप्रकार की मुद्रास्फीति उपभोक्ताओ के कारण उत्पन्न होती है।

कारण :– ① मुद्रा की आपूर्ति मे वृद्धि

(ii) अर्थव्यवस्था मे मुद्रा आपूर्ति मे वृद्धि होती है जिसमे संपुर्ण मांग बढ़ती है जिसके परिणाम स्वरूप मुद्रास्फीति बढ़ती है।

② **Increase in Forex Reserve**
विदेशी मुद्रा भंडार मे वृद्धि

यदि किसी अर्थव्यवस्था मे अधिक विदेशी मुद्राओ का भंडार होता है जिससे तरलता में वृद्धि होती है जिसके परिणाम स्वरूप मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है।

③ Increase in Government Expenditure

सरकारी व्यय मे वृद्धि

जब सरकार अर्थव्यवस्था में मुद्रा की वृद्धि करती है तब इससे अर्थव्यवस्था मे अधिक मुद्रा की आपूर्ति है जिससे परिणाम स्वरूप मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है।

④ Due to Fisical

राजकोषिय प्रोत्साहन के कारण :-

राजकोषीय प्रोत्साहन का उदाहरण है जब सरकार एक मुश्त राशि अर्थव्यवस्था मे लगाती है. जो बजट के अलावा राशियाँ होती है उससे मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है

Exa- Covid-19 के दौरान ~~सीता~~ निर्मला सीतारमण ने देश की अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए 20 लाख करोड रूपये जो कुल GDP का 10% था अर्थव्यवस्था में दिये इसे राजकोषीय प्रोत्साहन था हेलीकॉप्टर Money भी कहते है।

⑤ Depreciation of Rupee

रुपये का मूल्यह्रास

$1 = 50 रु

$1 = 70 रु

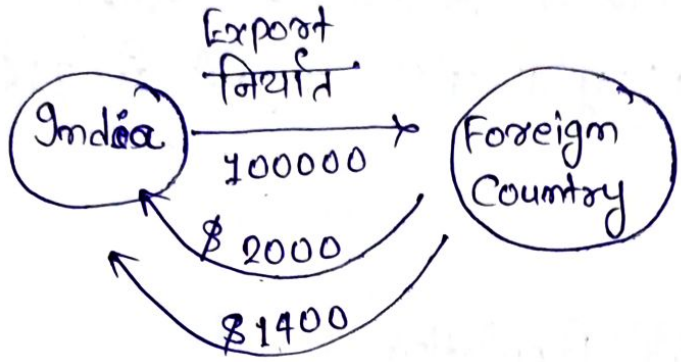

मुद्रा के मूल्य ह्रास से भारतीय Product वस्तुएँ ~~विदेश~~ बाजार में प्रतिस्पर्धी हो जाती है भारत की निर्यात मे वृद्धि होती है। जिससे विदेशी मुद्रा भंडार मे वृद्धि होती है।

⑥ Decrease in Saving

बचत में कमी

लोग कम बचत करते है तो इसका अभिप्राय यह है कि लोग अधिक व्यय कर रहे होते है। एवं जिससे अर्थव्यवस्था मे मुद्रा आपूर्ति मे वृद्धि होती है।

(7) Black Money / Fake Currency

काला धन

समानांतर अर्थव्यवस्था भी कहते हैं।

यदि अर्थव्यवस्था में अधिक काला धन होता है तो मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि होती है।

(8) Increase in Population

जनसंख्या वृद्धि

अधिक जनसंख्या के कारण अर्थव्यवस्था में अधिक माँग होगी मुद्रा की आपूर्ति होती है।

(9) Deficit Financing

घाटे का वित्तपोषण

जब सरकार के व्यय राजस्व से अधिक होते हैं तब कहा जाता है बजटीय घाटा जाता है। एवं इस बजटीय घाटे का वित्तपोषण निम्न

(a) RBI द्वारा नई मुद्रा जारी कर।

(b) ऋण लेकर

(10) प्रत्यक्ष करों मे कमी

Cost - Push Inflation

~~लागत जनित मुद्रास्फीति~~ लागत जनित मुद्रा०

↓

(उत्पादक)

जब अर्थव्यवस्था मे उत्पादन की लागत मे वृद्धि होती है। जिसके परिणाम स्वरूप आपूर्ति वस्तुओं की कम होती है जिसे लागत जनित मुद्रास्फीति कहते है।

इसके निम्नलिखित कारण है।:—

(1) उत्पादन के कारकों की कीमत मे वृद्धि
साधनों

उत्पादन के साधनों के कीमत मे वृद्धि भुमि, श्रम, पूंजी, संगठन। उद्यमी इनकें साधन लागत मे वृद्धि होती है जिसके परिणाम स्वरूप वस्तुओं के उत्पादन मे कमी होती है तथा वस्तुओं के मुल्य मे वृद्धि होती जिसके कारण मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है।

② वस्तुओं की जमाखोरी और सट्टेबाजी

जमाखोरी और सट्टेबाजी से मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है। जमाखोरी के कारण वस्तुओं की मात्रा मे कमी हो जाती है सट्टेबाजी के द्वारा वस्तुओं को सस्ते दामों मे खरीदकर मंहगे दामो मे बेचा जाता है।

③ दोषपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला / आपूर्ति आघात अड़चन / संरचनात्मक

जब आपूर्ति अचानक से कम हो जाए एवं मांग समान रहे तो इसे अड़चन Bottleneck कहते है।

जब अर्थव्यवस्था मे बुनियादी ढांचे का अभाव होता है एवं संरचनात्मक विकास नही होता है।

ठीक प्रकार सड़के न होना, बिजली ट्रांसपोर्ट मे रुकावट आती है, जिसके परिणाम स्वरूप संपूर्ण आपूर्ति कम हो जाती है।

* मांग जनित

<u>अप्रत्यक्ष करो में वृद्धि</u> (प्रत्यक्ष करो मे कमी)

अप्रत्यक्ष कर उत्पादकों पर लगाये जाते है जैसे GST एवं करो में वृद्धि के कारण उत्पादन लागत में वृद्धि होती है जिससे वस्तुओं का उत्पादन कम होता है।

\# $1 = 50 मुद्रा का मूल्य ह्रास :—
$1 = 70

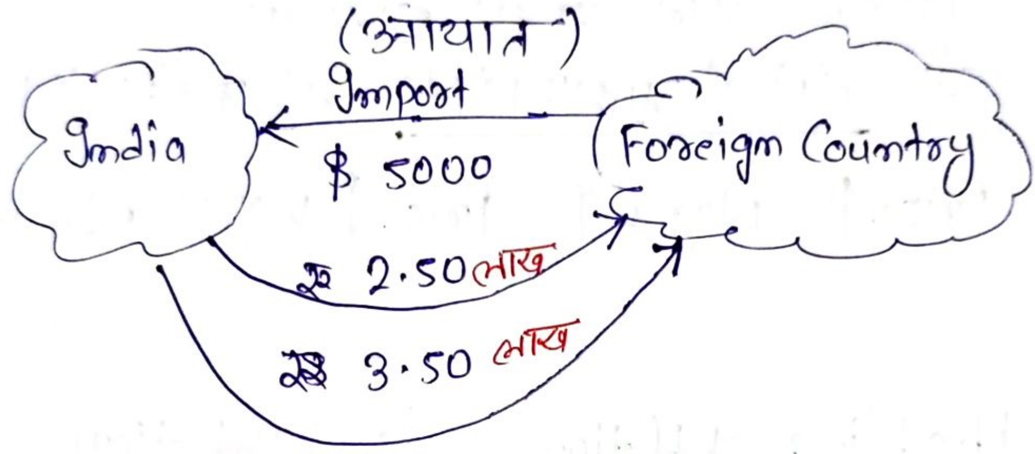

① * मुद्राकामुद्रा ह्रास से लागत में वृद्धि हो जाती है जिससे उत्पादन लागत मे वृद्धि हो जाती है।

② कच्चे तेल की कीमतों मे उतार /चढ़ाव

आयातित मुद्रास्फीति :—

तेल की किमतो मे वृद्धि होने से आयात मंहगे होगे जिससे आयातित मुद्रास्फीति कहते है।

Higher Wages
(उच्च मजदूरी)

उच्च मजदूरी के कारण मुद्रास्फीति मे वृद्धि।

निर्मित मुद्रास्फीति

मजदूरी – मूल्य :— निर्मित मुद्रास्फीति
(Wage – Prize) अर्थव्यवस्था में एक लगातार होने वाली अवस्था है।
इसे Spiral मुद्रास्फीति भी कहते है।

Prize↑ Wages↑ Price↑ Wages

Head line Inflation (हेडलाइन मुद्रास्फीति)	Core Inflation (मूलभूत मुद्रास्फीति)
① सभी वस्तुएँ एवं सेवाओं की कीमत बढ़ती है ईधन एव खाद्यान वस्तुओं को भी शामिल करते है।	वस्तुए एवं सेवाएँ की किमते बढ़ती है। खाद्यान एवं ईधन पदार्थों की किमतो को छोड़कर।

Skewflation (स्क्यूफ्लेशन मुद्रास्फीति)

वस्तुएं और सेवाओं के कीमतें बढ़े एवं अर्थव्यवस्था में कुछ वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें घटे Skewflation कहते है।

Phillips Curve

फिलिप्स वक्र

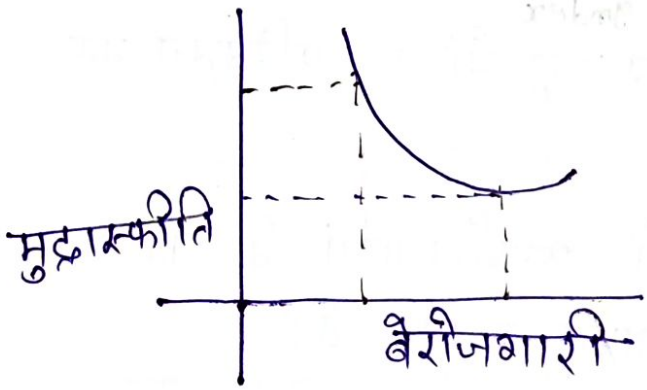

संबंध ⇊
नकारात्मक
(– ve)

इसका सिद्धांत A·W फिलिप्स ने 1958 में दिया था।

मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी के बीच नकारात्मक संबंध बताया था।

Date
21/Aug/23

मुद्रास्फीति को मापने के विधियाँ

① उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI)
- ग्रामीण [448]
- शहरी [460]

② थोक मूल्य सूचकांक (WPI) [697]

③ GDP अपस्फीति कारक

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI)

Consumer Price Index

यह भारत में खुदरा मूल्यों में परिवर्तन का मापन करता है।

यह अर्थव्यवस्था में उपभोक्ताओं के लिए मुद्रास्फीति का मापन करता है।

Types of CPI
CPI के प्रकार

- CPI औद्योगिक श्रमिक — Base year 2016
- CPI ग्रामीण श्रमिक — Base year 1986–1987

(दोनों) श्रम एवं रोजगार मंत्रालय (Labour Bureau श्रम ब्यूरो)
Ministry of Labour Employment MOLE

- CPI कृषि श्रमिक
  - CPI - ग्रामीण
  - CPI - शहरी
  - CPI – ग्रामीण + शहरी (संयुक्त)

Ministry of Statistics Programme Implementation
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय MOSPI

NSSO

National Sample Survey office
राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय

1950

इसका काम पूरे देश से अलग अलग जगहों से आकड़ा एकत्रित करना।

CSO

Central Statistical office
केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय

1951

NSSO के द्वारा आकड़ो को एकत्रित करने के बाद मापन का कार्य।

NSO

National Statistical office
राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय

23 मई 2019

NSSO + CSO → NSO

Number of Items
मदो की संख्या

Rural Area
ग्रामीण क्षेत्र

448 Goods & Services

Urban Area
शहरी क्षेत्र

460 Goods & Services

शीर्षक	भार
खाद्य और पेय पदार्थ	45.86%
पान तम्बाकू और नशीले पदार्थ	2.38%
कपडे और जुते चप्पल	6.53%
आवास	10.07%
इंधन और प्रकाश	6.84%
मिश्रीत (सेवायें)	28.32%

WPI
Wholesale Price Index
थोक मूल्य सूचकांक

यह वस्तुओ के थोक किमतो का मापन करता है।
यह उत्पादकों एवं थोक विक्रेताओ के लिए मुद्रास्फीति का मापन करता है।

→ भारत मे इसका मापन आर्थिक सलाहकारी कार्यालय (OEA) उद्योग एवं आन्तरिक व्यापार को बढ़ावा देने के लिए विभाग DPIIT Department for Promotion of Industry & Internal trade.

→ वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के द्वारा मापा जाता है। MOCI द्वारा।
Ministry of Commerce and Industry

→ WPI का आधार वर्ष 2011-2012, पहले 2004-2005 था।

Number of Items

697 Only Goods

शीर्षक	भार
* प्राथमिक वस्तुएँ (अनाज, फल, सब्जियाँ, खनिज)	22.62%
* ईंधन और विद्युत शक्ति (कोयला, बिजली, खनिज तेल)	13.15%
निर्माण उत्पाद (Manufacturing Product)	64.23%

Note:- भारत में मुद्रास्फीति के मापन का मुख्य सूचकांक : CPI - संयुक्त

⇒ CPI को अधिक महत्व देने का कारण
इसमें खुदरा किमते शामिल होती है।
इसमें सेवाएँ शामिल होती है।

⇒ CPI मे अधिक भार वस्तुएँ को दिया जाता है (46%) एवं WPI मे खाद्यय पदार्थों का भार कम है।

⇒ वर्तमान में (July 2023) में मुद्रास्फीति दर ~~4.4~~ 7.44% है।

उत्पादक मूल्य सूचकांक
Producer Price Index
(PPI)

⇒ यह उत्पादको को प्राप्त होने वाले किमतो मे परिवर्तन को मापता है जो उसे घरेलु एवं अन्तराष्ट्रीय बाजार मे प्राप्त होती है।

⇒ इसमें वस्तुएँ एवं सेवाएँ दोनो शामिल होती है।

⇒ B.N Goldar समिति ने PPI से संबंधित सिफारिश दी।

⇒ भारत मे मुद्रास्फीति के मापन के लिए प्रयोगतत्मक आधार वर्ष PPI का प्रयोग करना चाहिए।

इसमें वस्तुओं को भी शामिल करना चाहिए।

= **WFPI**

Wholesale Food Price Index

थोक मूल्य खाद्य सूचकांक

इसे 2017 मे प्रारम्भ किया गया है।

इसका मापन DPIIT के द्वारा होता है।

Department for Promotion of Industry and Internal Trade

⇒ **CFPT**

Cosumer Food Price Index

उपभोक्ता मूल्य खाद्य सूच्कांक

NSO द्वारा मापन

National Statistical office

अनाज एव उत्पाद - CPI खाद्य मूल्य सूचकांक की गणना मे सर्वाधिक भार - 34.2%.

⇒ **FAO**

Food and Agriculture Organistaion

खाद्य और कृषि संगठन

FAO खाद्य किमत सूचकांक

संयुक्त राष्ट्र के अन्तर्गत आता है।

यह अन्तराष्ट्रीय स्तर पर खाद्यन किमतो में परिवर्तन को मापता है।

इसमे वनस्पति तेल, मास, डेयरी उत्पाद, चीनी एवं अनाज की किमते शामिल होते है)

Point to Point Method / Year on Year Method

$CPI = \frac{P_1}{P_0} \times 100$

P_1 = Current year Price

P_0 = Base year Price

$CPI = \frac{550}{500} \times 100$

July 2023 – Rs 550

July 2022 – Rs 500

$= 110 = 10\%$

CPI Base year = 2012

* वर्तमान भारत मे मुद्रास्फीति के दर को इसी विधी से मापा जाता है।
* इसमें वर्तमान वर्ष के माह के सदर्भ मे पिछले वर्ष के इसी माह से किमतों में परिवर्तन की तुलना होती है।

मुद्रास्फीति के प्रभाव

(1) अमीर और गरीब

मुद्रास्फीति मे आय एव धन का पुर्नी वितरण अमीरो को अनुकूल होता है क्योकि अल्प विकसित, विकासशील भारत मे आय का वितरण अधिक असमान है। जिसके परिणाम स्वरूप अमीरो को लाभ एवं गरीबो को हानि होता है।

(2) निश्चित और परिवर्तनशील आय समूह

निश्चित आय समूह मे (वेतन भोगी, पेंशन भोगी आदि) एवं लचीली आय समूह में सेवा प्रदान करने वाले आदि शामिल होते है। एवं मुद्रास्फीति मे लचिली आय समूह मे वृद्धि होती है।

(3) उत्पादक और उपभोक्ता

उत्पादक को लाभ होता है एवं उपभोक्ता को हानि होती है।

(4) लेनदार (ऋणदाता) & देनदार (ऋणी)
(लोन देने वाला) (लोन लेने वाला)

मुद्रास्फीति मे मुद्रा की क्रय शक्ति कम हो जाती है जिससे ऋणी द्वारा ऋणदाता को वापस की गई मुद्रा से उतना लाभ प्राप्त नही होता जिसके परिणामस्वरूप मुद्रास्फीति ऋणी के अनुकूल एवं ऋणदाता के प्रतिकूल होती है।

(5) **छोटे और बड़े किसान**

छोटे किसान उपभोक्ताओं के समान होते है क्योंकि ये आमतौर पर स्वयं उपयोग के लिए खेती करते है एवं बड़े किसान उत्पादको के समान होते है इसलिए मुद्रास्फीति मे बड़े किसानों को अधिक फायदा होता है।

(6) शेयर धारक और डिबेंचर / बॉन्ड धारक

मुद्रास्फीति मे शेयर धारकों को अधिक किमते प्राप्त होती है।

(7) **भुगतान संतुलन BOP**

→ **अनुकूल** (Favourble)

→ **प्रतिकूल** (Unfavourble)

Expoot > Import

Export < Import
↓
Inflation

मुद्रास्फीति में भारत के निर्यात अन्तर्राष्ट्रीय बाजार मे कम प्रतिस्पर्धित होते है, इसलिए निर्यात कम होती है।

(8) विदेशी विनिमय दर

अधिक आयात एवं कम निर्यात के कारण से विदेशी मुद्रा में मूल्यह्रास होता है।

(9) रोजगार पर

अल्पकालीन समय मे मुद्रास्फीति एवं रोजगार के बीच सकरात्मक संबंध होता है। लेकिन यह दीर्घकालीन समय मे संभव नही।

(10) बचत पर

मुद्रास्फीति मे वस्तुओ एवं सेवाओ की कीमते बढ़ जाती है जिससे लोगो के व्यय मे वृद्धि होती है एवं जिसके परिणाम स्वरूप बचत कम होती है।

Date :- 22/Aug/23

Fiscal Policy
राजकोषीय नीति

यह वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा बनाई जाती है। इसे बजटीय नीति भी कहते हैं।

इस नीति के द्वारा सरकार अपने राजस्व एवं व्यय के द्वारा अर्थव्यवस्था मे मुद्रास्फीति का

राजकोषीय नीति के उद्देश्य :-

कीमत स्थिरता

सरकार अपने व्यय एवं राजस्व के द्वारा अर्थव्यवस्था में तरलता का नियंत्रित करके सामान्य कीमतों में स्थिरता लाती है।

आर्थिक संमृद्धि (Economic Growth)

राजकोषीय नीति का मुख्य उद्देश्य है, अर्थव्यवस्था मे आर्थिक समृद्धि को बढ़ाना अर्थात् उत्पादन स्तर मे वृद्धि करना जिससे सरकार अर्थव्यवस्था में निवेश को बढ़ाकर GDP को प्रोत्साहित करती है।

आय का समान वितरण
Equal Distribution Income

सरकार अपने राजस्व एवं व्यय के द्वारा अर्थव्यवस्था मे आय का समान वितरण करती है।

अविकसित / विकासशील देशो मे लोगों के बीच आय का वितरण अत्यधिक असमान होता है।

आय का समान वितरण निम्न प्रकार से किया जा सकता है। :—

(a) अमीरो पर अधिक कर लागू करके
(b) गरीबों पर कर को कम करके
(c) विभिन्न योजनाओं के द्वारा निर्धनो को वित्तीय आय प्रदान करके।

(4) रोजगार की अवसर प्रदान करने के लिए — सरकार द्वारा विभिन्न तरीको से रोजगार के अवसरो को बढ़ाया जा सकता है।

(a) अधिक से अधिक सार्वजनिक क्षेत्रो में उद्यमों की स्थापना करके।

(b) निजी क्षेत्रो को अधिक से अधिक सब्सिडी प्रदान करे एवं करो की कटौती करके।

Fiscal Policy
राजकोषीय नीति

सरकार का व्यय	सरकार के राजस्व
① लोक निर्माण (Public Work)	① Tax
② लोक कल्याण (Public Welfare)	② विनिवेश
③ सैना (Defence)	③ लोक ऋण Publing Borrowing
④ सब्सिडी (Subcidies)	Govt. Bonds Ex – NSC, KVP etc

मुद्रास्फीति (Inflation)	अवस्फीति (Deflation)
① सरकार के व्यय ↑	① सरकार के व्यय ↑
② Tax ↑	② Tax ↓
③ विनिवेश ↑	③ विनिवेश ↓
④ लोक ऋण ↑	④ लोक ऋण ↓
* आधिशेष	* विस्तारवादी
* संकुचित	

राजकोषीय नीति के प्रकार

सकुचित राजकोषीय	विस्तारवादि राजकोषीय	तटस्थ राजकोषीय
① सकुचित राजकोषीय नीति सरकार व्यय कम < राजस्व ज्यादा	① सरकार का ~~[illegible]~~ व्यय ज्यादा (>) राजस्व कम	सरकार के व्यय एवं राजस्व में कोई परिवर्तन नहीं।
② अधिशेष बजट Surplus Budget	② अवस्फीति	
	③ घाटे का बजट Deficit Budget	

Date
23/Aug/23

Sub Prime Crisis / Sub Prime Landing

⇛ यह एक अवस्था है जब किसी देश की Bank कुछ ऐसे लोगों को Loan दे देती है जिनकी उन ऋणों को वापस करने की क्षमता नही होती है, उसे Sub Prime Landing कहते है।

⇛ यह 2008 मे USA मे देखा गया जिसके कारण वहा की कुछ बडी बैंकें जैसे - Layman Brother's जैसी बैंकों को अत्याधिक घाटा हुआ एवं वह बंद हो गई।

Fiscal Clip

यह Sub Prime संकट से सम्बधित है अमेरिका की कांग्रेस ने आर्थिक गति विधि को बढ़ावा देने के लिए मंदी की अवधि के दौरान कर कटौती के कानून बनाये, लेकिन एक समय सीमा तय कर दी गई अर्थात् 31 Dec 2012 की आधी रात तक

1 जनवरी 2013 में सरकार ने अचानक से कर दर को बढ़ा दिया एवं इन बढ़ी हुई कर दरों एवं कम सार्वजनिक व्यय के द्वारा आर्थिक संकट की समस्या को कम किया गया।

Fiscal Drag

अमीरों पर करों की दरों को बढ़ाकर अर्थात् अधिक कर राजस्व के द्वारा अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करना।

Fiscal Consolidation (राजकोषीय समेकन)

जब सरकार अपने घाटों और ऋणों ~~एकसाथ~~ को एकसाथ नियंत्रित करे।

Fiscal Glide

राजकोषीय समेकन को चरण बद्ध तरीके से लागू करना।

Fiscal Slippage
(राजकोषीय फिसलन)

जब सरकार अपने निर्धारित किये हुए घाटो के लक्ष्यों को प्राप्त न कर पाये।

Monetary Policy
मौद्रिक नीति

मौद्रिक नीति समिति

2016 मे निर्माण

उर्जित पटेल समिति के द्वारा

⇒ MPC के लिए RBI अधिनियम - 1934 खंड 45 ZB को शामिल किया गया।

⇒ MPC मे 6 सदस्य होते है।

① Chairman (RBI Governor).

② MPC के प्रभारी (Incharge) RBI के डिप्टी गवर्नर मे से कोई एक

③ RBI के निदेशको मे से एक

④ जयंत R वर्मा

(5) आशिमा गोयल
(6) शंशाक भिडे

⇒ ये 6 सरकार के सदस्य

⇒ सरकार के सदस्यों को चार (4) सालों के लिए मनोनीत करते है।

⇒ एक वर्ष मे ~~लगभग~~ कमसे कम चार बार बैठक होना अनिवाय है।

⇒ प्रत्येक बैठक मे चार सदस्य होना अनिवार्य है।

⇒ यदि कोई निर्णय नही हो पाता है तो RBI के पास निर्णायक मत होता है।

Monetary Policy

Quantitive / General Instument मात्रात्मक / सामान्य उपकरण	Quantitive Selective Instrument गुणात्मक चयनात्मक उपकरण
(1) Bank Rate (2) Repo Rate (3) MSF (4) RRR (5) SDP (6) CRR (7) SLR (8) open Market operation (OMO) मुक्त बाजार प्रचालन खुले बाजार की प्रक्रिया	(1) Margine Requirment सीमान्त आवश्यकता (2) Rationting of credit Regulation (साखों की राशनींग) (3) उपभोक्ता साख विनियमन (4) Moral pressure / sussion (5) Direct action

Date
24/Aug/23

Bank Rate :— यह वह दर है जिसपर RBI सभी वाणिज्य बैंको को दीर्घ कालीन ऋण देती है।

⇒ बैंक दर मे बैंको को RBI के पास वाणिज्यक विपत्र रखने होते हैं इसलिए हम बैंक दर को Rediscounting off Commercial Bill. भी कहते है।

⇒ वर्तमान मे यह 6.75% है

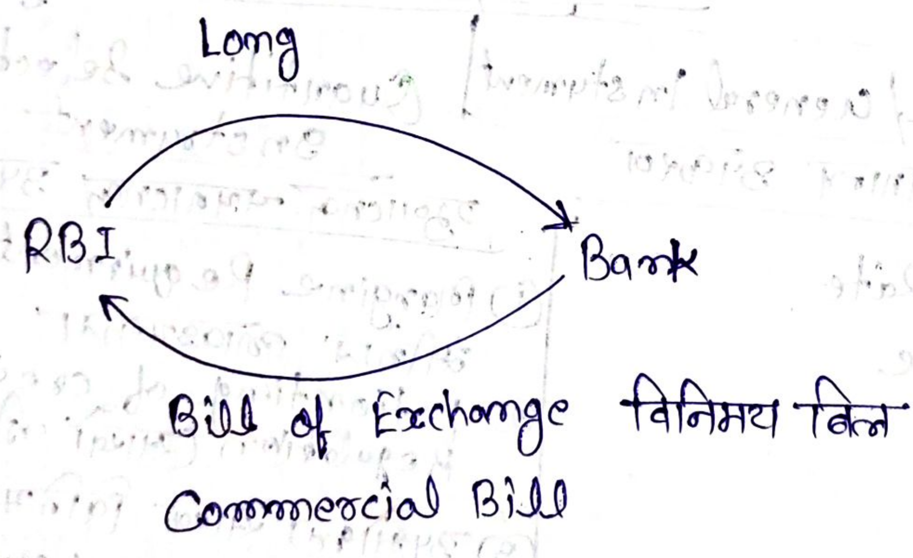

Repo Rate :- यह वह दर है जिसपर RBI सभी वाणिज्य बैंकों को अल्पकालीन ऋण देती है।

⇒ इसमें बैंको को सरकारी प्रतिभूति RBI के पास रखनी होती है।

⇒ आमतौर पर इसका प्रयोग बैंक अपने धन के अस्थाई नगद प्रवाह अन्तर को कम करने के लिए करती है।

⇒ इसे 1992 मे प्रारंभ किया गया।

⇒ रेपो रेट को बैंचमार्क Policy Rate भी कहते है क्योंकि इसके द्वारा RBI मौद्रिक नीति एवं मौद्रिक संचरण तंत्र को लागू करती है।
Monetary transmission Mechanism

रेपो रेट

1% off Bank NDTL

Overnigh Repo	Term Repo
	3 day, 7 day 14 day 28 day
0.25% of NDTL	0.75% NDTL

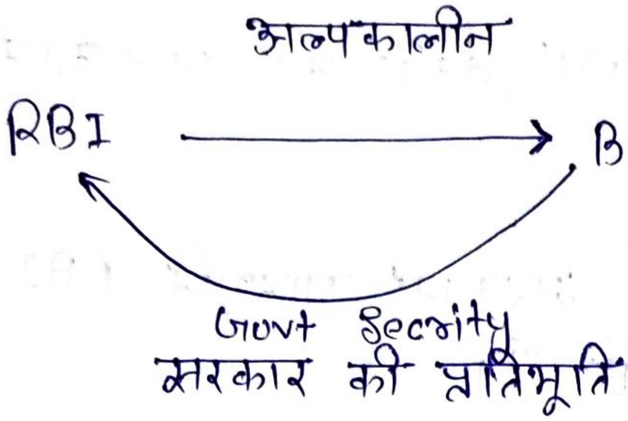

Net Demand time Liabilities
शुद्ध / निबल मांग एवं सावधि देयता / दायित्व

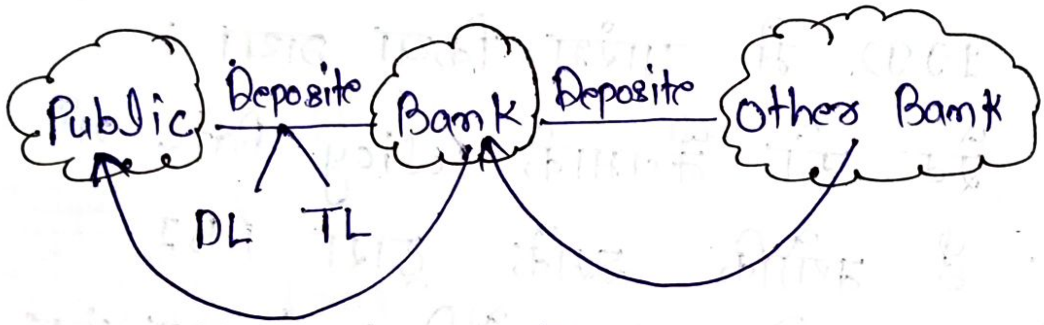

MSF Margin Standing Facility
सीमांत स्थाई सुविधा

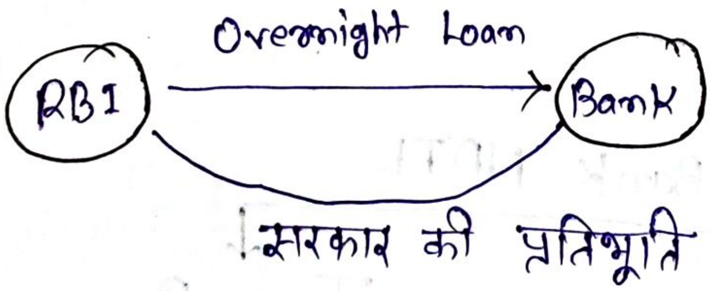

2 % NDTL

यह वह दर है जिसपर RBI सभी वाणिज्य बैंक को एक रात्रि प्रणनत Overnight प्रदण देती है।

यह 2011 मे लाया गया।
यह बैंक का NDTL का अधिकतम 2% तक हो सकता है एवं 1 करोड के गुणांक मे

2011 मे MSF बैंक रेट के समान होता है।
यह हमेशा रेपो रेट से ज्यादा होता है

Reverse Rapo Rate
(विपरीत रेपो दर)

इसे स्थाई विपरीत रेपो दर कहते है।
RBI यह वह दर है जिसपर RBI बैंको से ऋण लेती है। एवं RBI को सरकारी प्रतिभूति रखनी होती है।
आमतौर पर इसका प्रयोग तब होता है जब बैंको के पास तरलता अधिक होता है।
यह हमेशा रेपो दर से कम होगा।
यह 1996 से प्रारंभ हुआ।

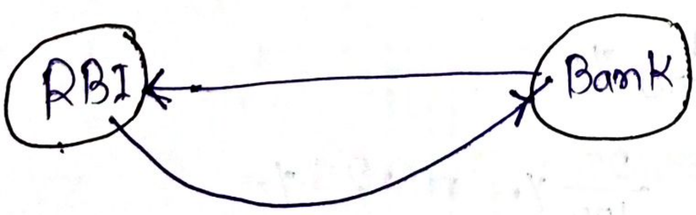

Excess Deposite
अतिरिक्त जमा
तरलता ↑

SDF Standing Deposit Facility
स्थाई जमा सुविधा

इसकी घोषणा 2018-19 बजट
लागू — 2022

⇒ इसे RBI अधिनियम 1934 खंड-17 में संशोधित करके शामिल किया गया।

⇒ इसमे बैंके अपनी अतिरिक्त जमाओं को रखती है लेकिन इसके बदले RBI बैंकों को कोई सरकारी प्रतिभूति नही देता।

⇒ यह बैंकों के पास एक प्रकार की Uncollaterised गैर संपादिक सवरक जमा सुविधा है।

⇒ आमतौर पर RBI इसका प्रयोग बाजार से अतिरिक्त तरलता को कम करने के लिए करती है।

⇒ RBI ने यह घोषणा कि यह रेपो रेट से 0.25% कम होगा।

Basis Point (Bps)

$1 \text{ bps} = \frac{1}{100}\%$

$25 \text{ bps} = \frac{25}{100}\% = .25\%$

Date 23/Aug/23

CRR 4.5%

Cash Reserve Ratio

प्रत्येक वाणिज्यक बैंको को अपनी कुल जमाओं का न्यूनतम प्रतिशत RBI के पास रखना होता है।

यह RBI अधिनियम 1934 के खंड 42 (2) के अन्तर्गत आता है।

RBI, CRR की जमाओं पर कोई ब्याज नही देता।

2006 मे CRR की न्यूनतम तथा अधिकतम सीमाओं को समाप्त कर दिया गया
यह सिर्फ नकद के रूप मे हो सकता है।

SLR 18%

वैधानिक तरलता अनुपात

प्रत्येक वाणिज्यक बैंको को अपनी कुल जमाओं का एक निश्चित प्रतिशत रखना होता है

~~यह सिर्फ नगद~~ Section 24 (2A)

यह बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 खंड 24 (2A) के अन्तर्गत आता है।

यह नगद या तरल संपत्तियों मे रखा जा सकता है।

Gold, Govt Bond, Foreign सरकारी प्रतिभूतियाँ

2007 मे SLR की न्यूनतम सीमा को समाप्त कर दिया लेकिन यह 40% तक हो सकता है।

Open Market Operation (OMO)

मुक्त बाजार प्रचलन

इसका अभिप्राय है कि सरकार की प्रतिभूतियों को RBI एवं बैंक के बीच खरीदना या बेचना

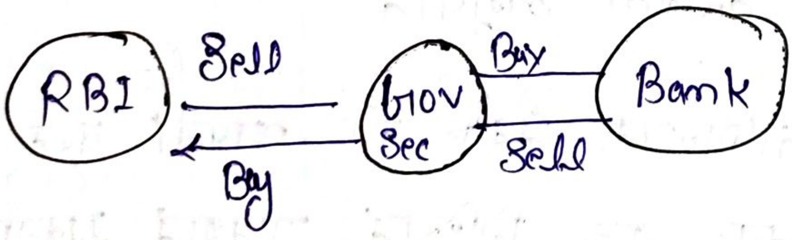

Qualitative Instruments
गुणात्मक चयनात्मक

① सीमात आवश्यकता :— बैंकों द्वारा RBI
Margin Requirement को दि गई प्रतिभूति का मूल्य एवं RBI द्वारा बैंकों को दिये गये ऋण के बीच का अन्तर

② साख की राशनिंग :— RBI द्वारा बैंकों के
Rationing of Credit विभिन्न गतिविधियों के लिए निर्धारित किये जाने वाला ऋण का कोटा।

Priority Sector Landin Norm
प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को दिये जाने वाले ऋण सम्बन्धित नियम

हमारे देश मे 8 प्राथमिकता वाले क्षेत्र है।

① कृषि — 18%
② MSME — 7.5 कमजोर वर्ग 12%
③ Education
④ आवास

⑤ निर्यात वित्त
⑥ नवीकरणीय ऊर्जा
⑦ समाजिक अवसंरचना
⑧ अन्य / मिश्रित

] Loan Amount Total 40 %

Cusumer Credit Regulation
उपभोक्ता साख विनियमन

बैंको द्वारा अपने ग्राहको को दिये जाने वाले ऋण सम्बाधित नियम कानूनों को बनाया जाता है।

Moral Pressure
नैतिक तनाव

RBI बैंको द्वारा अपने बनाये गए नियम कानून का पालन करने को कहती है। (लिखीत / मौखित)

Direct Action
प्रत्यक्ष कार्यवाही

~~यदि~~ यदि RBI द्वारा बनाई गई नितियों को बैंक अनुपालन नही करती है तब RBI के पास उनके लाइसेंस का जब्त करने का या पेनल्टी लगाने का

अधिकार होता है।

MS↑	Inflation	Deflation	MS↓
Dear/Tight	Bank Rate ↑	↓	Cheap
Hawkish	Repo Rate ↑	↓	Easy/Loose
महगी मौद्रिक	Marginal (MSF) ↑	↓	Dovis/
नीति	Reverse Rapo Rate ↑	↓	Accomodative
	SDF ↑	↓	मौद्रिक निती
	CRR ↑	↓	मिलनसार
Direct Intrument प्रत्यक्ष उपकरण (← CRR, SLR)	SLR ↑	↓	
	SEL ↑	↓	
	BUY ↑	↓	

~~Date~~ 28/Aug/23

गैर-पारंपरिक मौद्रिक नीति

Non Convestion Monetary Policy

1. Helicopter Money हैलीकाप्टर मुद्रा

~~2. Quan~~ * इसका सिद्धांत Miltan Fridman द्वारा दिया गया था।

- इसका प्रयोग अर्थव्यवस्था मे मुद्रा की आपूर्ति को बढ़ाने के लिए किया जाता है।

- हेलीकाप्टर मुद्रा मे RBI बडी मात्रा में धन की छपाई करती है एवं जनता में वितरण करती है।
- आमतौर पर इसका प्रयोग मंदी के दौरान अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने के लिए किया जाता है।
- इसमे दि गई रकम वापस नही ली जाती है।

Quantitative Easing

मात्रात्मक सहजता

जब RBI बैंकों मे एक विशिष्ट मात्रा मे प्रतिभूतियां को खरीदती है एवं इस प्रकार से अर्थव्यवस्था मे तरलता को बढाया जाता है।

Fed Tapering

Fed Federal Reserve

Fed Tapering का तात्पर्य Federal Reserve द्वारा सम्पति की खरीद को धीरे-धीरे कम करना है। अर्थात् मात्रात्मक सहजता की प्रक्रिया को धीमा करना।

Operation Twist

यह US पद्धति पर आधारित है एवं सर्वप्रथम इसका प्रयोग 1961 US ने किया था।

भारत में इसे 2019 में प्रयोग किया।

आपरेशन Twist मे केंन्द्र बैंक दीर्घकालीन प्रतिभूतियां को बैंकों से खरीदती है एवं साथ में अल्पकालीन प्रतिभूतियों को बेचती है।

इसका प्रयोग अर्थव्यवस्था में दीर्घकालीन ब्याज दरों को कम करने के लिए होता है।

Swith Operation

जब RBI अल्पकालीन प्रतिभूतियों को खरीदती है एवं दीर्घकालीन प्रतिभूतियों को बेचती है।

Incremental CRR
वृद्धिशील CRR

इसका प्रयोग RBI अर्थव्यवस्था में अतिरिक्त तरलता को नियंत्रित करने के लिए करता है।

- RBI ने 16 Sep 2016 – 11 | Nov | 2016 तक ICRR – 100%
- 19 May 2023 – 28 July 2023 – 10% ICRR

2016 – विमुद्रीकरण

Market Stabilisation Scheme
बाजार स्थिरीकरण योजना

- इसे 2004 में प्रारंभ किया गया।
- अर्थव्यवस्था में अतिरिक्त तरलता को कम करने के लिए RBI द्वारा Bank को प्रतिभूतियों को बेचना

MSS	OMO मुक्त बाजार प्रचलन
Only sell	By Sell
तरलता ↓	तरलता ↑↓

Long Term Repo Operation
दीर्घकालीन रेपो प्रचलन

- इसे 2020 में प्रारम्भ किया गया भारत में।
- इसे सर्वप्रथम 2008 में यूरोपियन केन्द्र बैंक ने किया था।
- तरलता को बढ़ाने के लिए।
- LTRO में Bank RBI से 1-3 वर्षों के लिए ऋण ले सकती है।

प्रशासनिक नीति
Administrative Policy

* सट्टा और जमाखोरी पर प्रतिबंध
* प्रत्यक्ष मूल्य नियंत्रण * अनिवार्य वस्तुओं की किमत निर्धारित करना।
* बफर स्टॉक का उपयोग।
* निर्यात पर प्रतिबंध
* घरेलु आपूर्ति के पूरक के लिए।